

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3297
जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है
ईवी चार्जिंग स्टेशन

3297. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक एकल राष्ट्रव्यापी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करने की कोई योजना है;
- (ख) क्या सरकार ने चार्जिंग मैं लगने वाले लंबे समय को कम करने के लिए तीव्र चार्जिंग प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) वर्तमान में देशभर में प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या तथा किसी भी समय बंद पड़े स्टेशनों का प्रतिशत कितना है;
- (घ) ईवी चार्जिंग स्टेशनों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने अतीत में बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याओं की सूचना दी है; और
- (ड) सरकार ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाले बिजली कटौती के मुद्रे पर किस तरह से ध्यान दे रही है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार के विद्युत मंत्रालय ने देश में जनता के लिए स्थापित किए गए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों का एक राष्ट्रीय ऑनलाइन डेटाबेस विकसित करने के उद्देश्य से 'ईवी यात्रा' पोर्टल शुरू किया है, जिससे ईवी प्रयोक्ता निकटतम चार्जिंग स्टेशनों को ट्रैक कर सकें। 'ईवी यात्रा' पोर्टल www.evyatra.beeindia.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।

(ख) राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 के तहत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और विनिर्माण के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा को बढ़ाना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। एनईएमएमपी 2020 के हिस्से के रूप में, सरकार ने निम्नलिखित दो चरणों में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना को लागू किया है।

i. चरण-I को 31 मार्च, 2019 तक 895 करोड़ रुपये के बजट के साथ लागू किया गया था। योजना के पहले चरण में, लगभग 2.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 359 करोड़ रुपये (लगभग) की कुल मांग प्रोत्साहन राशि की सहायता दी गई थी। इसके अलावा, योजना के पहले चरण के तहत स्वीकृत 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें, लगभग 280 करोड़ रुपये के सरकारी प्रोत्साहन से देश के विभिन्न शहरों में तैनात की गई हैं। सरकार ने फेम इंडिया योजना के चरण-I के तहत 43 करोड़ रुपये (लगभग) की लागत से लगभग 520 चार्जिंग स्टेशन/अवसंरचना को भी मंजूरी दी थी।

ii. चरण- II को 11,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2024 तक पांच वर्षों के लिए लागू किया गया था। योजना के तहत ई-2पहिया, ई-3पहिया और ई-4पहिया सहित कुल 16,71,606 ईवी बेचे गए हैं। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न शहरों/राज्य परिवहन उपकरणों (एसटीयू)/राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए शहर के भीतर परिचालन हेतु 6862 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की हैं। 6862 ई-बसों में से 5,140 ई-बसें योजना के तहत शुरू की गई हैं। इसके अलावा, फेम-II योजना के तहत 10,985 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 18 मार्च, 2025 तक देश भर में 26,367 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। पीसीएस का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के साथ 40-60 किलोमीटर के अंतराल पर मार्गस्थ सुविधाएं विकसित करने की परिकल्पना की है, जिसमें अनिवार्य सुविधाओं में से एक के रूप में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का प्रावधान है। स्थापित की गई ऐसी चार्जिंग सुविधाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार ने फेम-II योजना के तहत 60/120 किलोवाट क्षमता वाले 534 फास्ट ईवी ईवीपीसीएस शुरू किए हैं। ये ईवीपीसीएस पूरे भारत में हैं।

(घ) सरकार ने भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और देश में इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में तेजी लाने के लिए अखिल भारतीय आधार पर निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं।

- i. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रीवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना: 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना को 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया था। यह 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली दो साल की योजना है, जिसका उद्देश्य ई-2पहिया, ई-3पहिया, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता और परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन करना है। इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव योजना में विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये की सहायता की परिकल्पना की गई है।
- ii. भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (पीएलआई-ऑटो): सरकार ने 23 सितंबर, 2021 को भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए

भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु इस योजना को अनुमोदित किया है। यह योजना न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) के साथ एटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य शृंखला में निवेश आकर्षित करती है।

iii. एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई योजना: सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से देश में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य 50 गीगावाट एसीसी बैटरियों के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।

iv. पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना: 28 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित इस योजना का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में सहायता करना है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीएएस) द्वारा चूक की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

V. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15 मार्च, 2024 को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% और पांचवें वर्ष के अंत में 50% का डीवीए हासिल करना होगा।

इसके अलावा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

क. इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है।

ख. बैटरी से चलने वाले वाहनों को ग्रीन लाइसेंस प्लेट दी जाएंगी और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

ग. राज्यों को ईवी पर सडक कर की छूट देने का परामर्श देते हुए अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिससे ईवी की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

घ. इसके अलावा, राज्य सरकारें ईवी की खरीद पर प्रोत्साहन भी दे रही हैं।

(ड.) ईवी चार्जिंग स्टेशनों की बिजली आपूर्ति से संबंधित किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान देश की अखिल भारतीय बिजली आपूर्ति स्थिति का विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

अनुबंध-।

‘इवी चार्जिंग स्टेशनों के संबंध में’ श्री एंटो एंटनी द्वारा दिनांक 20-03-2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3297 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य	एनएच नं.	स्थल विवरण	इवी चार्जिंग सुविधा की स्थिति
1	हरियाणा	दिल्ली-मुंबई	डीडी2-3एल_पैकेज3_63+140 एलएचएस	शुरू किया गया
2	हरियाणा	दिल्ली-मुंबई	डीडी2-4आर_पैकेज3_69+900 आरएचएस	शुरू किया गया
3	राजस्थान	दिल्ली-मुंबई	डीडी3-5आर_पैकेज5_125+600 आरएचएस	शुरू किया गया
4	राजस्थान	दिल्ली-मुंबई	डीडी3-5एल_पैकेज5_125+600 एलएचएस	शुरू किया गया
5	हरियाणा	ट्रांस-हरियाणा	एके1-1एल_पैकेज1_21+100 एलएचएस	शुरू किया गया
6	हरियाणा	ट्रांस-हरियाणा	एके1-2आर_पैकेज1_21+100 आरएचएस	शुरू किया गया
7	हरियाणा	ट्रांस-हरियाणा	एके1-3एल_पैकेज2_50+650 एलएचएस	शुरू किया गया
8	हरियाणा	ट्रांस-हरियाणा	एके1-4आर_पैकेज2_50+650 आरएचएस	शुरू किया गया
9	हरियाणा	ट्रांस-हरियाणा	एके2-5एल_पैकेज4_93+530 एलएचएस	शुरू किया गया
10	हरियाणा	ट्रांस-हरियाणा	एके2-6आर_पैकेज4_93+530 आरएचएस	शुरू किया गया
11	हरियाणा	ट्रांस-हरियाणा	एके2-7एल_पैकेज5_120+400 एलएचएस	शुरू किया गया
12	हरियाणा	ट्रांस-हरियाणा	एके2-8आर_पैकेज5_120+400 आरएचएस	शुरू किया गया
13	हरियाणा	ट्रांस-हरियाणा	एके3-9एल_पैकेज6_152+500 एलएचएस	शुरू किया गया

14	हरियाणा	ट्रांस-हरियाणा	एके3-10आर_पैकेज6_152+500 आरएचएस	शुरु किया गया
15	हरियाणा	ट्रांस-हरियाणा	एके3-11एल_पैकेज7_191+600 एलएचएस	शुरु किया गया
16	हरियाणा	ट्रांस-हरियाणा	एके3-12आर_पैकेज7_191+600 आरएचएस	शुरु किया गया
17	उत्तर प्रदेश	एनई2	कुंडली - पलवल /एनई2_39+500_आरएचएस_मिलक चकरपुर_गाजियाबाद	शुरु किया गया
18	उत्तर प्रदेश	एनई3	यूपी/डीएमई/01 गाजियाबाद, यूपी	शुरु किया गया
19	उत्तर प्रदेश	एनई3	यूपी/डीएमई/02 गाजियाबाद, यूपी_36+250 आरएचएस	शुरु किया गया
20	उत्तर प्रदेश	एनई2	कुंडली - पलवल /एनई2_39+500_एलएचएस_मिलक चकरपुर_गाजियाबाद	शुरु किया गया
21	कर्नाटक	40	बेलगाम-महाराष्ट्र सीमा खंड/एनएच- 4/589+731/एलएचएस/बेलगाम जिला/केए	शुरु किया गया
22	कर्नाटक	63	बेल्लारी- गुंतकल खंड/एनएच-63/365-360/एलएचएस/बेल्लारी जिला/केए	शुरु किया गया
23	तमिलनाडु	45	उलुदुरपेट - तिंडीवनम /एनएच45/186+400/आरएचएस/ परिक्कल /तमिलनाडु	शुरु किया गया
24	तमिलनाडु	44	एनएच44/टीएन/245+050/एलएचएस/सलेम/तमिलनाडु	शुरु किया गया
25	असम	27	एएस/एल/02/एनएच-27 नागांव , असम	शुरु किया गया
26	असम	27	एएस/एस/02/एनएच-27/ नागांव - काजीरंगा /278.663/एलएचएस/ उरीगांव (रोटरी के पश्चिम)/ नागांव /असम	शुरु किया गया
27	असम	27	एएस/एस/03/एनएच-27/ नागांव - काजीरंगा /278.663/आरएचएस/ उरीगांव (रोटरी के दक्षिण)/ नागांव /असम	शुरु किया गया
28	गुजरात	दिल्ली-मुंबई	वीके1-31एल_पैकेज3_306+530 एलएचएस	शुरु किया गया
29	गुजरात	दिल्ली-मुंबई	वीके1-32आर_पैकेज3_317+930 आरएचएस	शुरु किया गया

30	ગુજરાત	દિલ્લી-મુંબઈ	વીકે2-18આર_પૈકેજ2_346+070 આરએચએસ/ સરસ્વામી	શુરુ કિયા ગયા
31	ગુજરાત	દિલ્લી-મુંબઈ	વીકે2-17એલ_પૈકેજ2_347+410 એલએચએસ/ ગોરિયાડ	શુરુ કિયા ગયા
32	મધ્ય પ્રદેશ	60	બંદ્ટાર- ખલઘાટ /એનએચ-3/63+300/આરએચએસ/ ધાર જિલા/મપ્ર	શુરુ કિયા ગયા
33	મધ્ય પ્રદેશ	319	એનએચ-30_358+100_આરએચએસ_મદનપુરા_એમપી	શુરુ કિયા ગયા
34	રાજસ્થાન	દિલ્લી-મુંબઈ	ડોડી4-6એલ_પૈકેજ6_172+550 એલએચએસ	શુરુ કિયા ગયા
35	રાજસ્થાન	દિલ્લી-મુંબઈ	ડોડી4-6આર_પૈકેજ6_172+550 આરએચએસ	શુરુ કિયા ગયા
36	રાજસ્થાન	દિલ્લી-મુંબઈ	ડોડી4-47એલ_પૈકેજ7_195+000 એલએચએસ	શુરુ કિયા ગયા
37	રાજસ્થાન	દિલ્લી-મુંબઈ	ડોડી4-47આર_પૈકેજ7_195+000 આરએચએસ	શુરુ કિયા ગયા
38	રાજસ્થાન	12	ટોંક - દેવલી /એનએચ-12/157+100/એલએચએસ/ ટોંક_આરજે	શુરુ કિયા ગયા
39	રાજસ્થાન	12	ટોંક-દેવલી /એનએચ-12/81+000/આરએચએસ/ ટોંક /આરજે	શુરુ કિયા ગયા
40	રાજસ્થાન	48	એનએચ-48/20.057+20.357 /આરએચએસ/જયપુર/રાજસ્થાન/ શ્રીગોવિંદપુરા	શુરુ કિયા ગયા
41	રાજસ્થાન	48	એનએચ-48/20+432 સે 20+732 /એલએચએસ/જયપુર બાઈપાસ/રાજસ્થાન/ બિલોંચી	શુરુ કિયા ગયા
42	તમિલનાડુ	45બી	મદુરૈ - તૂતીકોરિન /એનએચ45બી/142+400_આરએચએસ/મદુરૈ/તમિલનાડુ	શુરુ કિયા ગયા
43	મધ્ય પ્રદેશ	દિલ્લી-મુંબઈ	કેજે3/દિલ્લી-વડોદરા/પૈકેજ21/589+086/આરએચએસ	શુરુ કિયા ગયા
44	મધ્ય પ્રદેશ	દિલ્લી-મુંબઈ	કેજે3/દિલ્લી-વડોદરા/પૈકેજ21/589+086/એલએચએસ	શુરુ કિયા ગયા
45	કર્નાટક	63	બેલ્લારી- ગુંતકલ ખંડ/એનએચ-63/292+480/એલએચએસ/બેલ્લારી જિલા/કેએ	શુરુ કિયા ગયા
46	મધ્ય પ્રદેશ	75	એનએચ-75/76/સીએચ-126+172 /આરએચએસ/ પલોથા / છતરપુર /એમપી	શુરુ કિયા ગયા

47	राजस्थान	148-सी	एनएच-148सी/चै.31+500/आगरा और अजमेर रोड के बीच/ रातल्या /आरजे	शुरू किया गया
48	राजस्थान	148-सी	एनएच-148सी/चै.12+300/आगरा और अजमेर रोड के बीच/ सिरोली /आरजे	शुरू किया गया
49	उत्तर प्रदेश	एनई2	कुडली - पलवल /एनई2_95+575_आरएचएस_औरंगपुर_ गाजियाबाद	शुरू किया गया
50	उत्तर प्रदेश	एनई2	कुडली - पलवल /एनई2_95+600_एलएचएस_ औरंगपुर_गाजियाबाद	शुरू किया गया

‘ईवी चार्जिंग स्टेशनों के संबंध में’ श्री एंटो एंटनी द्वारा दिनांक 20-03-2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3297 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थापित सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस)

क्र. सं.	राज्य का नाम	पीसीएस की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	4
2	आंध्र प्रदेश	614
3	अरुणाचल प्रदेश	44
4	असम	311
5	बिहार	393
6	चंडीगढ़	14
7	छत्तीसगढ़	290
8	दिल्ली	1951
9	गोवा	155
10	गुजरात	1008
11	हरियाणा	808
12	हिमाचल प्रदेश	114
13	जम्मू और कश्मीर	157
14	झारखण्ड	277
15	कर्नाटक	5879
16	केरल	1288
17	लद्दाख	1
18	लक्षद्वीप	1
19	मध्य प्रदेश	942
20	महाराष्ट्र	3842
21	मणिपुर	50
22	मेघालय	43
23	मिजोरम	13
24	नगालैंड	36
25	ओडिशा	550
26	पुदुचेरी	42

27	पंजाब	607
28	राजस्थान	1285
29	सिक्किम	11
30	तमिलनाडु	1495
31	तेलंगाना	976
32	त्रिपुरा	54
33	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश	6
34	उत्तर प्रदेश	2113
35	उत्तराखण्ड	202
36	पश्चिम बंगाल	791
कुल		26,367

‘ईवी चार्जिंग स्टेशनों के संबंध में’ श्री एंटो एंटनी द्वारा दिनांक 20-03-2025 को पूछे गए लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3297 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी 2025 तक) के दौरान अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति
का विवरण:

वर्ष	ऊर्जा			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	%
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	
2021-22	1,379,812	1,374,024	5,787	0.4
2022-23	1,513,497	1,505,914	7,583	0.5
2023-24	1,626,132	1,622,020	4,112	0.3
2024-25* (फरवरी, 2025 तक)	1,547,785	1,546,229	1,555	0.1

*फरवरी, 2025 का डेटा अनंतिम है।
